Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 General Impact Factor : 2.4668, Volume 04, No. 01, January-March., 2018, pp. 325-327

राजस्थान में महिला शिक्षा उत्थान हेतु सरकारी प्रयास

डॉ. प्रभुदयाल चौधरी *
राजकुमार चौधरी**

महिला इस समाज का अहम हिस्सा है। इस समाज के निर्माण में नारी का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में नारी को पूजा जाता था। उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता था। उसे पुरूषों के समान ही माना गया है। हर काम में नारी पुरूषों के समान ही भागीदारी रही है,फिर भी आज के दौर में महिला की दशा दयनीय बनी हुई है। शिक्षा के कारण ही नारी सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास कर सकती है, परन्तु आज नारी क्षेत्र की मुख्य बाधाएँ हैं महिलाओं का अशिक्षित होना, अधिकारों के प्रति उदासहीनता, सामाजिक कुरीतियाँ तथा पुरूषों का महिलाओं पर स्वामित्व इन सभी समस्याओं से छुटकारा एक नारी पाना चाहती है तो उसका एकमात्र साधन है शिक्षा। वर्तमान समय में यह महसूस किया जा रहा है कि नारी को शिक्षा दिलवाने में ठोस कदम उठाने होगें तभी समान विकास हो पायेगा। इसीलिए नारी–शिक्षा की दशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है।

वर्तमान में लड़कियों के लिये अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जा रहे है ताकि नारी भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। महिलाओं को शिक्षित बनाने का वास्तविक अर्थ है उसे सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाना ताकि उनका विकास हो सके। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वंय का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे सकती हैं। इसलिये आज लोक कल्याणकारी सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है। और उसे शिक्षित कर रहा हैं, ताकि देश उन्नति के पल पर आगे बड़े। राजस्थान राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहतर मानी जाती है लेकिन यह भी सच है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, घूंघट में छिपे चेहरों में आज आत्मविश्वास की इतनी ललक है कि हर क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिला कर चलने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। आंकडो पर यदि नजर डाली जाये तो 2011 की जनगणना में राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। जो देश की कुल जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या 3. 30 करोड़ है जो कि राज्य कि कुलजनसंख्या का 48 फीसदी है।

उद्देश्य

- राजस्थान में महिला शिक्षा के स्तर की जानकारी ।
- राजस्थान में महिला शिक्षा में उत्तरोक्तर वृद्धि की जानकारी ।
- राजस्थान में महिला शिक्षा हेतु किये गये सरकारी प्रयासों की जानकारी।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत लेख में द्वितियक समंको का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक संमको में पत्र–पत्रिकाओं (राजस्थान संदर्भ) एंव वार्षिक प्रतिवेदन (महिला एंव बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एंव जन सांख्यिकी विभाग) से प्राप्त आंकड़ो को सम्मिलित किया गया है।

* सह–आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।
** शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

- **राजस्थान की साक्षरता स्तर आजादी से आज तक (1951–2011)**

जनगणना वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)
1951	8.50	13.88	2.66
1961	18.12	20.08	7.01
1971	22.57	33.87	10.06
1981	30.11	44.77	14.00
1991	38.55	54.99	20.44
2001	60.41	75.70	49.85
2011	66.1	79.20	52.10

संदर्भ जनगणना–2011

- राजस्थान में स्वतंन्त्रता के पश्चात् ये महिला शिक्षा में उत्तरोतर वृद्वि हुई है। उस समय कुल साक्षरता दर 8.50 प्रतिशत थी जिसमे महिला साक्षरता दर केवल 2.66 प्रतिशत थी। आंकड़े बताते है कि राजस्थान की साक्षरता दर मे सर्वाधिक वृद्धि दर (1991–2001) वाले दशक में हुई। 1991–2001 वाले दशक में राजस्थान की कुल जनसंख्या में 22 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी दर्ज की गई जो राज्य की (2011) की जनगणना मे कुल साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत का लगभग एक तिहाई भाग है। राजस्थान देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। देश के सभी राज्यो में केवल बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमे महिला साक्षरता राजस्थान की महिला साक्षरता की दृष्टि से कम है।

राज्य मे महिला साक्षरता ने सार्वाधिक वृद्धि 1991–2001 वाले दशक में हुई। इस दशक में सरकार में शिक्षा मे बढोत्तरी करने हेतु अनेक प्रयास किये। जिसके परिणाम स्वरूप 2001 की महिला साक्षरता दर में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जो उस दशक में (1991–2001) पुरूष साक्षरता में हुई 22 प्रतिशत वृद्धि दर से भी 8 प्रतिशत अधिक थी। राज्य की वर्तमान 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर के जिलेवार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्रदेश के 18 जिलों में महिला साक्षरता की दर 50 प्रतिशत से भी कम है अर्थात इन जिलों में महिलाओं की कुल संख्या का आधे से अधिक भाग निरक्षर है। राज्य के केवल 3 जिले (कोटा, जयपुर,झुन्झुनू) में ही महिला साक्षरता दर के 60 प्रतिशत के आकड़े को छुआ है। राज्य में 3 जिले (जालोर, जैसलमेर, सिरोही) ऐसे भी हैं। जिनमे महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत से भी कम है। राजस्थान न्यूनतम महिला साक्षरता की दर वाले जिलों जालोर जिला 38.5 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जिला कोटा 65.9 प्रतिशत की है। राज्य में कुल साक्षरता के विषय में देखा जाये तो स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 2011 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता में 8 गुना वृद्धि हुई है। इसमें पुरूष साक्षरता में 6 गुना एवं महिला साक्षरता में 20 गुना वृद्धि हुई है। राजस्थान में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिये सरकार ने कई योजनाएँ प्रारम्भ कर रखी है। इन योजनाओं के फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में वृद्धि अवश्य प्राप्त की गई है। लेकिन महिला शिक्षा की दृष्टि से अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। शिक्षा के ग्राफ को बढ़ाने के लिए वर्तमान में निम्न कार्यक्रम संचालित है।

सर्व शिक्षा अभियान

विद्यालय तंत्र मे समुदाय की सहभागिता द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के लिये सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न सामजिक एवं लैंगिक भैदों को बाटने एवं विद्यालय में सभी बच्चो के शत प्रतिशत ठहराव का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में प्रारम्भिक विद्यालयो के प्रबन्धन में पंचायती राज्य संस्थाओ, विद्यालय प्रबन्ध समितियों, अभिभावक–अध्यापक संगठनो एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार (RTE)

6–14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीट्स पर असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है।

गार्गी पुरूस्कार

बालिका शिक्षा को प्रोत्सहान देने के लिये यह पुरूस्कार दिया जाता है। इसमें सैकण्डरी की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को तीन हजार रूपये एवं प्रमाण पत्र दिये जाते है।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरूस्कार

प्रत्येक जिले में अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन (सात वर्ग–प्रत्येक वर्ग की एक) बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक/प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उस बालिका को इन्दिरा प्रियदर्शेनी पुरूस्कार प्रदार किये जाते है।

मीना मचं

सरकार ने छठी से आठवींकक्षा तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को सम्मलित कर बाल विवाह दहेज पथा आदि सामाजिक मुद्दो के प्रति जागरूक किया जाता है। इस मंच के माध्यम से बीच मे ही शिक्षा छोड देने वाली छात्राओं को विद्यालय भेजने के लिये अनके अभिभावकों को प्रेरित किया जाता है।

अध्यापिका मंच

बालिकाओ के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और विद्यालय की छात्राओ के लियें मित्रवत् वातावरण स्थापित करने के लिये अध्यापिका मंचो का गठन किया गया।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

इस योजना के अन्तर्गत राजस्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक जिले में 02 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में कक्षा 11 व 12 की छात्राओं हेतु 15,000 रूपये एंव स्नातकोत्तर स्तर तक 25000 रूपये प्रतिवर्ष पुस्तकों, स्टेशनरी एंव गणवेश आदि के दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 व 12 की छात्राओं हेतु 1 लाख रूपये व स्नातकोत्तर स्तर तक 02 लाख रूपये महाविद्यालय शुल्क कोचिंग फीस व छात्रावास शुल्क आदि के लिये दिये जाते हैं।

वर्तमान में इस योजना का दायरा बढ़ाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में जिलों में सर्वोधिक अंक प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की एक बालिका को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

सरकार की इन प्रमुख कार्यक्रम/योजनाओं के कारण महिला साक्षरता में उछाल आया है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी तेजी की हरकार है। राजस्थान के दूरदराज के इलाकों की बात तो दूर बड़े शहरों में भी लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिये कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जहॉ 1991 की जनसंख्या में महिला साक्षरता केवल 20 फीसदी थी वह बढ़कर 2011 में 52 फीसदी हो गई है। वैसे साक्षरता दर में आई तेजी से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आयेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

~ महिला विकास एंव राजकीय योजनाएं, संगीता शर्मा, रितु।

~ वार्षिक प्रतिवेदन–महिला एंव बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर।

~ साक्षर महिलाएँ सामाजिक विकास का आधार प्रो. उषा पी. पटेल, रावत प्रकाशन।

~ महिला विकास के लिये योजनाएं, राजस्थान सरकार।

~ जनगणना–2011 भारत सरकार।

❑❑❑